

**Vision Statement**

“नवीन तकनीकों, क्षमता निर्माण एवं उत्तरदायी प्रशासन द्वारा भूमि प्रबंधन एवं छावनी क्षेत्रों को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करना”

Effective Land Management and Development of Cantonment Areas as Model Townships by deploying latest technologies, building capacities and ensuring responsible administration

**MISSION STATEMENT**

1. To leverage space technology and drone imagery in land management particularly for updating defence land records, mapping of defence land pockets, polygon reconciliation of survey numbers inside Cantonments and extracting features for urban planning of Cantonments.
2. To undertake pilot projects and gradually adopt Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) tools in land use optimization, change detection, planning and execution of public utility projects and minimizing manual intervention in work processes & regulatory functions.
3. To maximize Information Technology in all domain functions and processes of Defence Estates Organisation to attain highest efficiency, full transparency, ease of business for all stakeholders and ease of living for Cantonment residents including Military population.
4. To build capacities internally & for other Government organizations externally in latest land and urban management tools through National Institute of Defence Estates Management (NIDEM) and its Centre of Excellence (CoE) by bringing in knowledge partners.
5. To effectively protect defence land, remove or regularize encroachments, improve management of old grant and leased land, process land transfers for infrastructure and public utility projects within timelines and advise Government in evolving desired policy framework in management of all land cases, without adversely affecting security concerns of Armed Forces.
6. To effectively manage land acquisition processes and handle pre-post land acquisition cases with a view to minimize capital cost on acquisition and post-acquisition compensation cost.
7. To enable effective litigation management by DEOs to protect Government interest in the title suits, post-land acquisition litigation and other defence land disputes.
8. To be capable to undertake land surveys and land record management of other Central Government Departments as an expert agency.
9. To enhance the financial management capacity of Cantonment Boards by augmenting local revenue, obtaining requisite revenue share & grants from State Governments and receiving benefits of all Central & State Government infrastructure development & social welfare schemes while optimizing establishment expenditure.

10. To develop and maintain highest quality public infrastructure of Cantonment with greater emphasis on drinking water supply network, sewage lines & STP, drainage, schools, hospitals and dispensaries, Divyang Centres and old age homes.

11. To make Cantonments as model townships in India providing highest quality of life by adopting;

(a) Sustainable-

- building growth;
- solid and liquid waste management;
- smart municipal solutions.

AND

- (b)
- enhancing green cover;
  - addressing timely public grievances;
  - promoting ease of living.

12. To develop and maintain a repository of important and precious documents showcasing evolution of administrative, socio-cultural and military history of Cantonments.

13. To enable Cantonment Boards to strengthen Military-Civil liaison for a peaceful co-existence and improved quality of life for all residents.

## मिशन कथन

1. भूमि प्रबंधन विशेषकर रक्षा भूमि रिकार्डों को अपडेट करने, रक्षा भूमि पाकेटों की मैपिंग, छावनियों के अंदर सर्वे नंबरों का पॉलीगान मिलान तथा छावनियों की शहरी नियोजन के लिए विशेषताएं निकालने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा ड्रोन इमेज़नरी का लाभ उठाना।
2. प्रायोगिक परियोजनाएं चलाना तथा धीरे-धीरे भूमि के इष्टतम उपयोग, परिवर्तन का पता लगाने, सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं की योजना बनाने तथा कार्यान्वयन तथा कार्य प्रक्रियाओं व नियामक कार्यों में मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने में कृत्रिम इंटेलीजेंस व मशीन लर्निंग टूलों को अपनाना।
3. उच्च दक्षता, पूरी पारदर्शिता, सभी हितधारकों की बिज़नेस में आसानी तथा सैन्य आबादी सहित छावनी के निवासियों के लिए रहन-सहन में आसानी की प्राप्ति के लिए रक्षा सम्पदा संगठन के सभी प्रमुख कार्यों और प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक बढ़ाना।
4. ज्ञान भागीदारों को लाकर राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन संस्थान तथा इसके उत्कृष्टता के केंद्र के माध्यम से नवीनतम भूमि तथा शहरी प्रबंधन टूलों में आंतरिक तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिए बाहरी रूप से क्षमताओं का निर्माण करना।
5. सशस्त्र सेनाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना रक्षा भूमि की प्रभावी संरक्षा, अतिक्रमण हटाना अथवा उसे नियमित करना, ओल्ड ग्रांट तथा लीज भूमि के प्रबंधन में सुधार, आधारभूत संरचना तथा सार्वजनिक उपादेयता की परियोजनाओं के लिए समयसीमा के अंदर भी हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करना तथा सभी भूमि मामलों के प्रबंधन में वांछित नीति बनाने में सरकार को परामर्श देना।
6. भू-अधिग्रहण प्रक्रियाओं की प्रभावी ढंग से व्यवस्था करना तथा भू-अधिग्रहण के पूर्व तथा अधिग्रहण उपरांत प्रतिकर लागत पर पूंजीगत लागत को कम करना।
7. स्वामित्ववादों, भूमि अधिग्रहण उपरांत मुकदमेबाज़ी, रक्षा भूमि संबंधी अन्यवादों में सरकार के हितों की रक्षा के लिए रक्षा सम्पदा अधिकारियों द्वारा मुकदमेबाज़ी प्रबंधन को प्रभावशील बनाना।

8. एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों का भू-सर्वे करने तथा भूमि रिकार्ड प्रबंधन करने में सक्षम बनाना।
9. प्रतिष्ठान के व्यय का इष्टतम प्रयोग करते समय स्थानीय राजस्व में वृद्धि करके, राज्य सरकारों से अपेक्षित राजस्व हिस्सेदारी तथा अनुदान प्राप्त करके तथा केंद्र व राज्य सरकार की सभी आधारभूत विकास व समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करके छावनी बोर्डों की वित्तीय प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना।
10. पेयजल आपूर्ति नेटवर्क, सीवरेज लाइनों तथा सीवरेज ट्रीटमेंट संयन्त्रों, नालों, स्कूलों, अस्पतालों तथा औषधालयों, दिव्यांग केन्द्रों व वृद्धावस्था आश्रमों पर अधिक जोर देकर छावनी के उच्च गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक ढांचे को विकसित करना।
11. भारत में छावनियों को आदर्श टाउनशिप के रूप में विकसित करने के लिए जीवन की उच्चतम गुणवत्ता को अपनाते हुए -

(ए) सतत-

- भवन निर्माण
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- स्मार्ट नगरपालिका समाधान

तथा

- (बी) - हरित आवरण को बढ़ाना  
- समय पर जनता की शिकायतों का समाधान  
- जीवन की सुगमता को बढ़ावा देना।

12. प्रशासनिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व छावनियों के सैन्य इतिहास के क्रमिक विकास को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण व बहुमूल्य दस्तावेजों का संग्रह विकसित करना तथा उसे अनुरक्षित करना।
13. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सैन्य-सिविल संबंधों को मजबूत करने तथा सभी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए छावनी बोर्डों को सक्षम बनाना।